भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 143
दिनांक 03 फरवरी, 2025

ईंधन की कीमतें

143# श्री नीरज डांगी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊर्जा वार्ता 2024 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत के अन्वेषण क्षेत्र को 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्वेषण और उत्पादन में निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए परिचालन और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्री जी के हाल ही में दिए गए इस वक्तव्य के मद्देनजर कि देश में वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं, पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों की तुलना अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से किस प्रकार से की जाती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार ने अन्वेषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें तथा अपस्ट्रीम सुधार किए हैं। नामांकन व्यवस्था (ऑयल एंड नेचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड + ऑयल इंडिया लिमिटेड) के तहत कुल सक्रिय रकबा 54,808 वर्ग किलोमीटर है तथा संविदा व्यवस्था [पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति/नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (उत्पादन साझाकरण संविदा), हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (राजस्व साझाकरण संविदा) और खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति (राजस्व साझाकरण संविदा)] के तहत कोल बेड मीथेन ब्लॉक सहित कुल सक्रिय रकबा 2,54,411 वर्ग किलोमीटर है।

इन पहलों के तहत, खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत आठ (08) बोली दौर पूरे हो चुके हैं और अब तक 2,42,056 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र वाले 144 ब्लॉक सफल बोलीदाताओं को प्रदान किए जा चुके हैं। सरकार ने 1,36,596 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 28 ब्लॉकों को कवर करते हुए ओएएलपी बोली दौर-IX की शुरूआत की है जिसके लिए 60 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(ख): भारत सरकार ने भारत के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससीज) का राजस्व साझाकरण संविदाओं (आरएससीज) में बदलाव, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा अधिक निवेशक-अनुकूल वातावरण को बनाना शामिल है। अन्य प्रमुख सुधारों और

प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी दरों में कमी, तेल पर उपकर नहीं लगाना, मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत ब्लॉक चयन में लचीलापन, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक संसाधनों के लिए एकल लाइसेंस, संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण की अनुमति तथा स्व-प्रमाणन एवं डिजिटलीकरण शामिल हैं।

(ग): भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों (भारतीय रुपये में) का अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तुलनात्मक डेटा पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण और विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय द्वारा संकलित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा समय-समय पर प्रकाशित मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

भारत, दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ हाल के वर्षों में पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों में कमी आई है। नवंबर 2021 से दिसंबर 2024 के बीच कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों में होने वाले बदलाव निम्नवत हैं:

	नवंबर-21 और दिसंबर-24 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का प्रतिशत	
देश	**पेट्रोल**	**डीज़ल**
भारत (दिल्ली)	**-13.60%**	**-10.92%**
फ्रांस	11.07%	10.99%
जर्मनी	3.40%	6.86%
इटली	5.21%	7.38%
स्पेन	5.14%	8.58%
यूके	0.17%	2.22%
कनाडा	5.55%	15.06%
यूएसए	1.36%	6.90%

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

नवंबर 2021 से दिसंबर 2024 के बीच कुछ पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बदलाव

	नवंबर-21 और दिसंबर-24 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का प्रतिशत	
देश	पेट्रोल	**डीज़ल**
भारत (**दिल्ली**)	-13.60%	-10.92%
पाकिस्तान	27.90%	33.37%
बांग्लादेश	12.62%	29.31%
श्रीलंका	54.29%	98.59%
नेपाल	20.06%	31.64%

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

*****